राज्यों में रेल विस्तार

*284 **श्री कपिल सिब्बल** : †

श्री राजीव रंजन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार को मार्च, 2000 तक देश के विभिन्न राज्यों में रेलमार्गों के विस्तार हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) किस-किस राज्य से कौन-कौन से रेलमार्ग बनाने की मांग की गई है;

(ग) यह मांग पहली बार सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी; और

(घ) अब तक प्रत्येक मांग के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दिग्विजय सिंह**) **:** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है गया है।

विवरण

(क) से (घ) रेलों पर निवेश संबंधी योजना राष्ट्रीय परिप्रेक्षय में बनाई जाती है। रेलवे के निवेशों के संबंध में निर्णय करने के लिए राज्यों की सीमाएं मानदंड नहीं होती है। बहरहाल, रेल नेटवर्क के विस्तार के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय समुचित ध्यान दिया जाता है। नई रेल लाइनों के लिए चल रही सभी परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिए परिशिष्ट** 190,**अनुपत्र सं**. 29 (**मूल संस्करण**)]

चूंकि विभिन्न राज्य रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न मंचों से मांगें करते रहे हैं, निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि कोई मांग विशेष पहली बार कब की गई थी। बहरहाल, मार्च, 2000 तक नई लाइनों के लिए प्राप्त हाल ही के प्रस्ताव, उन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [**देखिए परिशिष्ट** 190, **अनुपत्र सं**. 29, (**मूल संसकरण**)]

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह द्वारा पूछा गया।

Railway's Extension in States

† *284. SHRI KAPIL SIBAL:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH:@

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the proposals received by Government. by March 2000 for extension of Railway's in various States of the country;

(b) the name of States and of rail routes for which demands have been made by the States;

(c) when such demand was first submitted to Government; and

(d) the action taken in respect of each demand, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Investment Planning on the Railways is done in national perspective. State boundaries are not a criterion for deciding on Railway investments. However, proposals received from various States regarding expansion of Railway netwok are taken due note of while formulating proposals for Railway projects. Details of all ongoing New Line projects are given in Annexure. *[See Appendix 190, Annexure No. 29]*

Since States have been raising demands for works of extension of Railway network on various occasions and in different fora, it is not possible to exactly specify the date when a particular demand was first raised. However, recent proposals for New Lines received from the States upto March 2000 along with the action taken on these demands are given in Annexure. *[See Appendix 190, Annexure No. 29]*

---

† Original notice of the Question was received in Hindi.
@The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh.

श्री राजीव रंजन सिंह : सभापति जी, जवाब में मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके अनुपत्र सं. 29 (मूल संस्करण) में जो राज्यवार ब्यौरा है, उस ब्यौरे में विभिन्न राज्यों के लिए जो आवंटन दिया गया है, उसमें काफी असंतुलन है । एक राज्य विशेष को अत्यधिक आवंटन हुआ है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है और दूसरा यह कि इस वर्ष के कुल बजट का कितना प्रतिशत पश्चिम बंगाल को दिया गया है और शेष भारत को कितना आवंटन मिला है?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, एक तो रेलवे राज्यवार ब्यौरा नहीं रखती है । हमारा जो संसाधनों का बंटवारा होता है वह रेलों के हिसाब से होता है, रेलों के जो ज़ोन्स बने हुए हैं, उसके अनुसार होता है लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि जो बंटवारा है, वह असंतुलित उनको लगता है तो मैं माननीय सदस्य ने इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको पिछले साल से कम पैसा दिया गया था या पिछले तीन वर्षों के आंकड़े हम सदन के सामने रखें तो पिछले तीन-चार वर्षों में जिन राज्यों को जितना पैसा दिया गया, उससे ज्यादा ही पैसा उन राज्यों को अब दिया गया है । कम किसी को नहीं दिया गया है और जहां तक एक राज्य के बारे में आपने कहा है, तो इस बार उस राज्य में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे ने स्वीकार किया है ।

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, मैंने नई परियोजना के बारे में नहीं पूछा, मैंने कहा है कि जो आपने आवंटन किया है उसमें पूरे बजट की कितनी राशि पश्चिम बंगाल में दी है और कितनी राशि शेष भारत में दी है?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि अगर माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष के बारे में जानना चाहते हों तो हम उसका उत्तर देंगे । जिस राज्य से माननीय सदस्य का संबंध है वह बिहार है, बिहार के तीन वर्ष के आंकड़े मेरे पास हैं ।

श्री राजाव रंजन सिंह : मैं बंगाल क्षेत्र की परियोजना के बारे में पूछ रहा हूं और ये बिहार के बारे में बता रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : हमारा पैसे देने के लिए राज्यों में बंटवारा नहीं है । कोई रेल चलती है बंगाल से तो बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक आती है , पर कैसे कह दें कि कह बंगाल क्षेत्र की परियोजना है । कई राज्यों से गुजरते हुए रेल की परियोजना जाती है । यदि आपको अपने राज्य से परेशानी है कि वहां पर कम मिला है, आपका संबंध बिहार राज्य से है, और उसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसके आंकड़े मेरे पास हैं ।

1997-98 में 259 करोड़ रुपया दिया गया, 1998-99 में 238 करोड़ रुपया दिया गया, 1999-2000 में 255 करोड़ रुपया दिया गया और इस वर्ष 255,256 करोड़ के आसपास दिया गया है।

SHRI H. K. JAVARE GOWDA: Sir, you have taken construction of a new railway line, Hassan-Bangalore, in the Southern Railway Zone. It was taken up in 1997-98, at an estimated cost of Rs. 408.56 crores. Till the year 2000, the amount spent is Rs. 45.46 crores. The amount allocated for the year 1999-2000 is Rs. 20 crores. For the year 2000-2001, it is Rs. 9 crores. In the Hassan-Bangalore sector, there is a lot of scope for tourism and development. Looking at the scope, construction of the new railway line was taken up. This year, the allocation is hardly Rs. 9 crores. At this rate, it will take 55 years to complete the project. By the time it is completed, we will not be there to see it.

As far as the funding part is concerned, the Minister has said that he has requested the States to raise the funds. I would like to know if any money is raised from Karnataka for this particular railway line. If so, I would like to know the details and the funds raised by the State of Karnataka.

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल गंभीर सवाल उठाया है और हम यह बात पिछले काफी समय से कहते आ रहे हैं कि रेलवे को नई लाइन की परियोजनाओं के लिए जो कुल पैसे की जरूरत है वह करीब 22 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। रेलवे को अब तक इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम बजट में जो प्रावधान कर पाते थे वह मात्र 500 करोड़ रूपया होता था। इस बार हमने उस पैसे को बढ़ाया है और करीबन साढ़े 800 करोड़ रुपये के आसपास लागत को ले गए हैं। लेकिन अगर साढ़े 800 करोड़ रुपए को भी 22,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पूरा करना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपने तो 40-50 साल कहे लेकिन इसमें 40-50 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। जितना पैसा हम देते हैं उससे ज्यादा प्राइस एक्सक्लेशन हर साल हो जाता है। 10 परसेंट इनफलेशन का एक सामान्य रेट हम मानकर चलते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई हो रही है। इसलिए हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि आप अपनी प्राथमिकता बताएं ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले पैसा दिया जाए। मुझे खुशी है कि आपने जिस कर्नाटक राज्य की बात की है, उसमें राज्य सरकार ने तीन परियोजनाओं के लिए अपनी तरफ से

पैसा देने की बात कही है और उन परियोजनाओं को उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर बताया है कि इनको पूरा किया जाए । माननीय सदस्य का जिस रेल लाइन से संबंध है उस रेल लाइन में पैसा हमारे पास था 800 करोड़ रुपया और परियोजनाएं 22,000 करोड़ रुपए की । जितना हमारे पास पैसा था उस हिसाब से हमने दि दिया है । इसलिए यह कहना कि हमने उसको नजर अंदाज किया है, ठीक नहीं है ।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने जानकारी दी है इसमें पश्चिमी रेलवे की तीन रेलवे लाइनों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए । एक तो आपने इसी साल अजमेर-पुष्कर नई रेलवे लाइन डालने की व्यवस्था की है । इस पर 1,00,000,00 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और यह प्रोजेक्ट 67 करोड़ का है । रामगंज मंड़ी-भोपाल प्रोजेक्ट 425 करोड़ का है और इस पर भी आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है । इन दोनों का अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू हो गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अंतिम स्थान सर्वेक्षण का आकलन कब तक पूरा हो जाएगा?

दूसरा, एक बहुत ही मह्त्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि गोधरा, इंदौर, देवास, मक्सी का कुल 597 करोड़ का प्रोजेक्ट है । इसके लिए 21 करोड़ रुपये आपने अपने बजट में रखे हैं जिसमें से 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं तथा ये रुपये 31 मार्च तक आपको खर्च करने हैं किंतु आपने इसमें एक विचित्र सा प्रावधान डाल दिया है जो यह है कि यह खण्ड नौवीं योजना अवधि में पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों । मैं गम्भीरतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि यह 'बशर्ते' शब्द इसमें से कब निकलेगा क्योंकि यह योजना एक लंबे समय से चल रही है और इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आशावान हैं कि आपके माध्यम से हम पूरा-पूरा न्याय प्राप्त कर सकेंगे । इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दें ताकि इसका समाधान हो जाए ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, जहां तक अजमेर-पुष्कर से संबंधित सवाल पूछा गया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए अभी कम पैसे दिए गए हैं । जब तक फाइनल लोकेशन सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुछ दिन पहले ही फील्ड सर्वे का काम पूरा है चुका है अतः उसके बाद की प्रक्रिया हम अब आरंभ करेंगे । रामगंज मंडी के बारे में आपने पूछा ...(**व्यवधान**)...

श्री बालकवि बैरागी : रामगंज मंडी से भोपाल ।

श्री दिग्विजय सिंह : जी, जी । रामगंज मंडी से जो काम प्रारंभ हुआ है उसकी पूरी उम्मीद है कि वह पूरा हो जाएगा ।

तीसरा, आपने 'बशर्ते' शब्द हटाने की बात कही, मुझे प्रसन्नता होगी कि रेलवे की सारी परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें। लेकिन जो कठिनाई है वह भी हमने सदन के सामने रखी है ताकि एक रास्ता निकाला जाए। एक प्रस्ताव राज्य सरकारों के सामने भी रखा है कि यदि उनकी थोड़ी मदद मिल जाए, जैसे कोंकण रेलवे बनाने का काम हुआ था जिसमें चार राज्य सरकारे मिलीं, साथ मिलकर हमने एक बड़ी परियोजना, जो हिंदुस्तान के लिए गौरव की परियोजना है, पूरा किया। उसी तरह से यदि राज्य सरकारों का सहयोग मिल जाए जो कर्नाटक के लिए और तमिलनाडु के लिए मिला है तो यह भी हो सकता क्योंकि यह भी दो-तीन सरकारों का मामला है। अगर ये राज्य सरकारों और भारतीय रेलवे मिल जाए तो हम मिलकर बशर्ते शब्द को हटाने का भी प्रयास करेंगे।

SHRIMATI GEETHA VANGA: Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. I would like to know from the hon. Minister whether the Government propose to extend Secunderabad— Mehboobnagar rail service to Karnool. If so, when is it proposed to be started?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, राज्य सरकारों से हमने प्राथमिकता के लिए जिन कामों के बारे में कहा है उसमें अभी जिस पर्टिकुलर रेलवे लाइन के बारे में माननीय सदस्या ने पूछा है, उसका नाम मेरे सामने जो लिस्ट रखी है उसमें नही है। इसका लोकेशन सर्वे अभी हो रहा है और जैसे ही लोकेशन सर्वे हो जाएगा इस काम को प्रारंभ किया जाएगा।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister in his reply with regard to North-East Frontier Railway states that about Rs. 1,000 crores have already been sanctioned and the clearance of CCEA has also been obtained for the construction of Bogibeel Bridge over Brahamaputra. So far as clearance by the CCEA is concerned, it has been given after three years since the Prime Minister had laid the foundation stone of this project in 1997. Up till now, only Rs. 5 crores have been allocated for the purpose of investigation and survey. It has also been stated that it is expected that the detailed project report will be completed by the end of this year. The Railway Ministry is extending the date of commissioning of this project every year. I would like not know precisely from the hon. Minister whether he would ensure that this survey will be completed and the work will start from the month of January 2001? Sir, my second supplementary is, to press these demands, the Purbanchaliya

Rail Karmi Parishad staged a fast-unto-death strike in front of the NF Railway Headquarters at Maligaon on 9th. Instead of convincing them and discussing with the employees their demands, they were dragged by the Railway Police and they were brutally tortured. It was an unfortunate incident. I urge upon the Minister to take appropriate steps against the erring officers and also enquire into the matter and have discussions with the railway employees for an amicable solution of their problems.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, the hon. Member has put the question in two parts: part (a) and part (b). As far as the Bogibeel Bridge is concerned, as I have said in my written reply, the detailed investigation and final location survey has been taken up and the Cabinet Committee on Economic Affairs has also cleared this project. Model studies are in progress. But this is taking time because of the nature of these studies. So, we have to keep all these in mind. I assure you that the moment it is ready, the Railways will not lag behind. Part (b) of his question was regarding some atrocities by the RPF. I had been there 5-6 days back. I have not been told by any organisation there; two State Government Ministers were there, local M.P.s were there—nobody had informed me about this. If the hon. Member has any complaint against a particular employee of my Department, he can give me his name.

DR. ARUN KUMAR SARMA: This incident happened the day-before-yesterday. It is very unfortunate because the Railway Police has taken law into their hands. When the State Government is there, when the Police are there, they should have taken their help and some negotiations should have been there.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I would like to inform the hon. Member that so far as law and order is concerned, it is a State subject. Till 11 o'clock, the State Government has not complained anything against the RPF. If the complaint comes, I assure you, action will be taken against the concerned officers or personnel.

SHRI V.V. RAGHAVAN: Fifteen years ago, the foundation stone for the extension work of the Kuttipuram-Guruvayoor line

was laid. Sir, Guruvayoor is a pilgrim centre where the famous Sri Krishna temple is there.

MR. CHAIRMAN: Please put the question; otherwise, the Question Hour will be over.

SHRI V.V. RAGHAVAN: Sir, I would like know from the hon. Minister when this work will start.

SHRI DIGVIJAY SINGH: As the hon. Member is aware, I have just informed the House that we have the constraint of funds. If the State Government gives some indication that it is keen to have this project, and if they are prepared to share some of the cost for this particular project, we will definitely look into it and will complete it as soon as the Member desires.

SHRI KHAGEN DAS: Sir, if I understood Hindi properly, the Minister has just said that this year's Budget provision is more than what was provided during the last three years. But I am sorry to say that this is not the correct statement. The Budget provision, last year, for the Kumarghat-Agartala sector was Rs. 40 crores. What is the Budget provision for 2000-2001? Can the Minister tell me just now?

SHRI DIGVIJAY SINGH: You cannot ask me about a particular project. The hon. Member had asked me about projects State-wise. So, I had given the information that State-wise we have increased; we have not decreased for any State. Secondly, if you are keen to know about a particular project, I can pass on the information to you.

SHRI KHAGEN DAS: You have mentioned 'in any State'. What about my State?

SHRI DIGVIJAY SINGH: Which State are you talking about?

SHRI KHAGEN DAS: For my State of Tripura, last year's Budget was Rs. 40 crores. Now, this year, the Budget provision is Rs. 40 crores. So, the statement is not correct, Mr. Minister.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I can pass on the information to you. The figure is not....

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.